राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 08 अप्रैल 2026

वर्ष 14,अंक 347, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

डीजी अग्निशमन सुजीत पांडे को फोन और महज 10 मिनट में पहुंच गई मदद..03

जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा में त्रिकोणीय महायुद्ध, आख़िरी हँसी किसकी?..04

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

भवानीपुर में BJP का खेल, चक्रव्यूह में उलझीं ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी नहीं ये डेटा हैं सिरदर्द?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए अब तक की सबसे कठिन परीक्षा साबित हो रहा है. यह लड़ाई सिर्फ भाजपा उम्मीदवार और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट के बड़े बदलाव, डेमोग्राफिक शिफ्ट और वोटर डिलीशन के आंकड़ों के खिलाफ है. भवानीपुर हमेशा से ममता बनर्जी का गढ़ रहा है. लेकिन यह सीट अब राजनीतिक और प्रशासनिक चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है. भवानीपुर कोलकाता दक्षिण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. यहां बंगाली भद्रलोक वोट के साथ-साथ ठीक-ठाक संख्या में गैर-बंगाली व्यापारी समुदाय, गुजराती, पंजाबी और हिंदी भाषी रहते हैं. वर्ष 2011 से ममता यहां से लगातार जीतती आई हैं. 2021 के उपचुनाव में उन्होंने भाजपा की प्रियंका तिबरेवाल को रिकॉर्ड 58,832 वोटों के अंतर से हराया था. उस समय टर्नआउट करीब 57 फीसदी था और ममता को 85,263 वोट मिले थे. लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में स्थिति बदल गई. भवानीपुर असेंबली सेगमेंट में टीएमसी की लीड महज 8,297 वोटों की रह गई. भाजपा ने यहां के आठ में से पांच वार्डों में लीड हासिल की।

डेमोग्राफिक चेंज और एंटी-टीएमसी वोट

भवानीपुर में पहले करीब दो लाख वोटर थे. औसतन 60 फीसदी टर्नआउट पर करीब 1.20 लाख वोट पड़ते हैं. पिछले चुनावों के आंकड़ों के मुताबिक 45-50 फीसदी वोटर पारंपरिक रूप से टीएमसी के खिलाफ जाते रहे हैं. भाजपा अब इन गैर-बंगाली वोटर्स (लगभग 46 फीसदी) को टारगेट कर रही है. ये वोटर्स टीएमसी की 'ओनली बंगाली' छवि से खुद को दूर महसूस करते हैं. युवा और मोबाइल वोटर्स की बढ़ती संख्या ने भी पुराने वोट ब्लॉक्स को तोड़ा है. भाजपा का दांव गणित पर आधारित है. अगर ये वोटर्स एकजुट हो जाएं और इनके एकतरफा वोट टीएमसी मिले तो भवानीपुर में मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है. शुवेंदु अधिकारी 2021 में नंदीग्राम में ममता को हरा चुके हैं. वह अब भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार हैं. यह प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर दबाव है।

एसआईआर का सबसे बड़ा असर

इस सीट पर 47,000 वोटर डिलीट हुए हैं. लेकिन, असली सिरदर्द वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) है. भवानीपुर में SIR प्रक्रिया शुरू होने पर 2,06,295 वोटर थे. फाइनल लिस्ट में करीब 47,000 नाम डिलीट हो गए. इसके

अलावा 14,000 से ज्यादा वोटर्स 'अंडर एडजुडिकेशन' में हैं, जिनकी किस्मत दस्तावेज सत्यापन पर निर्भर है. यह संख्या 2021 के ममता की जीत के मार्जिन (58,000+) से सिर्फ 11,000 कम है. अगर इनमें से ज्यादातर टीएमसी समर्थक वोटर्स थे, तो पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है. टीएमसी ने इसे टारगेटेड कार्रवाई बताया है. ममता बनर्जी ने भी नाम कटने वाले वोटर्स से अपील करने की अपील की और इसे भाजपा की साजिश करार दिया. दूसरी ओर, भाजपा इसे क्लीन वोटर लिस्ट का अभियान बता रही है. पार्टी की राज्य महासचिव लॉकेट चटर्जी ने कहा कि केवल असली वोटर ही बंगाल का भविष्य तय करेंगे. भाजपा का मानना है कि SIR ने फर्जी वोटर्स को हटाकर असली गणित सामने लाया है।

ममता के लिए डबल चैलेंज

ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव अब सिर्फ शुवेंदु अधिकारी को हराने का नहीं रह गया है. उनका कैंपेन फीरहाद हाकिम संभाल रहे हैं. मैसेजिंग तेज है, आउटरीच ज्यादा डायरेक्ट है. लेकिन डेमोग्राफिक शिफ्ट और वोटर लिस्ट का बदलाव दोनों ही उनके लिए चुनौती हैं. मुस्लिम बहुल वार्ड 77 और 82 में टीएमसी अभी मजबूत है, लेकिन भवानीपुर के मध्य में झुकाव भाजपा की ओर दिख रहा है. शुवेंदु अधिकारी ने पहले ही दावा किया है कि एसआईआर के बाद वे भवानीपुर में ममता को 20,000 वोटों से हरा देंगे. अमित शाह की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करते समय भाजपा ने भवानीपुर में रोडशो किया, जो टीएमसी के गढ़ में सीधा संदेश था।

आगे क्या?

भवानीपुर अब सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति का टेस्ट केस बन गया है. अगर भाजपा यहां अच्छा प्रदर्शन करती है, तो यह टीएमसी की अजेय छवि को बड़ा झटका देगा. वहीं, अगर ममता बड़े मार्जिन से जीतती हैं तो वे साबित करेंगी कि उनका जनाधार अभी भी मजबूत है. वोटर लिस्ट में डिलीशन और एडजुडिकेशन का असर अंतिम मतदान प्रतिशत और वोट शेयर पर पड़ेगा. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि डेमोग्राफिक बैलेंस जहां हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, वहां वोटर में कोई भी चेंज राजनीतिक नतीजों को बदल सकता है।

महाराष्ट्रः गोंदिया में शराबबंदी की मांग पर उग्र हुए ग्रामीण, पुलिस पर पत्थरबाजी; करना पड़ा लाठीचार्ज

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव तहसील स्थित किंडगीपार गांव में शराब की दुकान को स्थायी रूप से बंद करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब उग्र हो गया है. आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान दोनों पक्षों के बीच टकराव हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जबकि पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज किया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि गांव के लोग पिछले करीब दो महीनों से शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इसी बीच 10 अप्रैल को रास्ता रोको और रेल रोको आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी. इसे देखते हुए पुलिस टीम मुख्य आंदोलनकारी संतोष दोनोडे के घर पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की नोटिस देने पहुंची थी।

पुलिस पर किया पथराव

पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे के मुताबिक, इसी दौरान संतोष दोनोडे ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की. इसके बाद जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो गांव के लोगों और पुलिस के बीच विवाद बढ़ गया. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

मुख्य आंदोलनकारी गिरफ्तार

वहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आंदोलनकारी संतोष दोनोडे समेत दो अन्य महिलाओं को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद किंडगीपार गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. गांव में भय का वातावरण बना हुआ है. वहीं ग्रामीणों ने 10 अप्रैल को बड़े आंदोलन की चेतावनी दोहराई है।

200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत, कोर्ट ने क्यों रखीं कुछ खास शर्तें?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर कोर्ट ने को जमानत दे दी है. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सुकेश की सुनवाई के दौरान कहा कि लंबे समय तक बिना वजह जेल में रखना व्यक्ति की आजादी और जल्द सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है. लेकिन जमानत के साथ ही अदालत ने कुछ खास शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 5 लाख रुपये के मुचलके और उतनी ही जमानत राशि जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

दरअसल, सुकेश को टू लीव्स सिंबल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत मिली है. फिलहाल उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं. अन्य मामलों के चलते वह बाहर नहीं आ पाएगा. उस पर करीबन 31 मामले दर्ज हैं, इनमें 26 में उसे जमानत मिल चुकी है. टू लीव्स सिंबल घोटाला सबसे चर्चित मामला रहा है. वहीं, कोर्ट ने इस मामले में आगे कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनके तहत उन्हें गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने से रोका गया है. साथ ही, उन्हें जांच अधिकारी को अपना पता और मोबाइल नंबर देने, अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर न जाने का निर्देश दिया गया है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, ये पूरा केस 200 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने और उसके पैसे को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़ा बताया जाता है. बताया जाता है कि टू लीव्स सिंबल घोटाला AIADMK का चुनाव चिन्ह पाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर पर कथित रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है. पुलिस के मुताबिक, सुकेश ने साल 2017 में AIADMK नेता टीटीवी दिनाकरन के लिए बिचौलिए का काम किया. उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव चिह्न हासिल करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के एक अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की. इस काम के लिए 1.3 करोड़ रुपये नकद भी बरामद किए गए थे. इसी मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर सुकेश चंद्रशेखर का नाम सामने आया. इसकी जांच ईडी कर रही है।

जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेगा सुकेश

जमानत मिलने के बाद भी सुकेश अभी जेल में बाहर नहीं आ सकेगा. दलअसल, सुकेश चंद्रशेखर को एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत तो मिल गई है, लेकिन बाकी मामलों की वजह से वह अभी जेल में ही रहेगा. उसके खिलाफ कुल 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 26 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. लेकिन 5 मामले अभी भी लंबित हैं, जिनमें वह जेल में हैं. इसलिए इस एक मामले में जमानत मिलने से उनकी रिहाई नहीं होगी. बताया जा रहा है कि लंबित मामलों में जमानत मिलने के बाद ही सुकेश जेल से बाहर निकल पाएगा।

संक्षिप्त ख़बरें

CEC नियुक्ति विवादः सुप्रीम कोर्ट ने तय की तारीख, 6-7 मई को होगी अंतिम सुनवाई

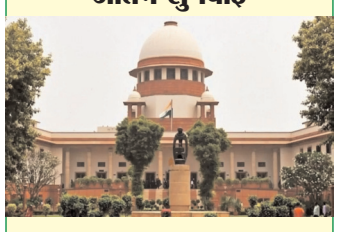

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीख तय की है. इससे पहले कोर्ट ने सरकार सहित सभी पक्षकारों को मामले में रिटन सबमिशन करने का निर्देश दिया था।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून के मुताबिक तीन सदस्यीय समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया जाना चाहिए. बता दें कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI की समिति की सलाह पर होनी चाहिए।

CJI ने सुनवाई से खुद को क्यों किया अलग?

मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस कानून पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इसमें हितों का टकराव है. मुझ पर इसका का आरोप लगाया जाएगा. अब यह मामला विचार-विमर्श के लिए एक नई पीठ को सौंपा जाएगा. सीजेआई सूर्यकांत ने ये भी कहा कि यह मामला एक ऐसी बेंच को सौंपा जाए, जिसमें जज चीफ जस्टिस बनने की रेस में न हो।

जनहित याचिकाओं में 2023 के कानून को चुनौती

दरअसल, जनहित याचिकाओं में 2023 के उस कानून को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति से सीजेआई को हटा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस कानून पर रोक नहीं लगाई है. अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी. याचिकाओं में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश का पैनल से बाहर होना नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता को कमजोर करता है. इस कानून को कांग्रेस नेता जया ठाकुर समेत कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है।

ड्यूटी से नदारद शिक्षिका ने वेतन के लिए रचा बीमारी का ढोंग, डीएम के सामने ओवरराइटिंग से खुली पोल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। एक डॉक्टर का कागज, उस पर बदली हुई कुछ स्याही...और उसी स्याही ने एक शिक्षिका के तर्कों को जिलाधिकारी के सामने ध्वस्त कर दिया। बीएलओ ड्यूटी में अनुपस्थित रहने के बाद वेतन रुकने से परेशान महिला शिक्षक जब अपनी सफाई लेकर जिलाधिकारी के सामने पहुंची, तो शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी-सी चूक उसे बड़ी कार्रवाई के मुहाने पर ला खड़ा करेगी। डॉक्टर के पर्चे पर ओवरराइटिंग करने और लगातार वरिष्ठ अधिकारी के सामने झूठ बोलने के मामले में जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिक्षिका की जांच करके कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

दो महीने पहले का है मामला

मामला 18 जनवरी 2026 का है, जब जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह विकास नगर स्थित जुगलदेवी सरस्वती इंटर कालेज के बूथ संख्या 243 का औचक निरीक्षण

करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान बीएलओ ड्यूटी पर तैनात सहायक अध्यापक उपासना सिंह ड्यूटी से गायब मिलीं थीं। एसआइआर जैसे संवेदनशील कार्य में लापरवाही पर डीएम ने उनका वेतन रोकने के आदेश दिए थे। शिक्षिका ने बीमारी का हवाला देकर वेतन जारी कराने का प्रयास किया। सोमवार को शिक्षिका प्रार्थना पत्र लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी के सामने पहुंचीं। प्रार्थनापत्र में उन्होंने बच्चों के बीमार होने का हवाला देते हुए डाक्टर का पर्चा लगाया। दावा किया गया कि बीमारी के कारण वह ड्यूटी पर नहीं पहुंच सकीं थी। जिलाधिकारी की नजर जैसे ही उस पर्चे पर पड़ी तो गड़बड़ी का अहसास हुआ। कागज पर लिखी तारीख और विवरण में ओवरराइटिंग साफ झलक रही थी।

स्याही के अलग-अलग रंग और लिखावट की असमानता ने संदेह को यकीन में बदल दिया। डीएम ने जब इस पर सवाल उठाया, तो शिक्षिका पहले तो जवाब देने से बचती रहीं, फिर बहस पर उतर आईं। कार्यालय का माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ प्रशासनिक सख्ती, दूसरी तरफ अपनी बात मनवाने की जिद। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब शिक्षिका अपने तर्कों पर अड़ी रहीं, तो जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए शिक्षिका को कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह को मामले की जांच करके नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए। शिक्षिका शिवराजपुर के भटपुरा विद्यालय में तैनात हैं, लगातार बीएलओ ड्यूटी का विरोध कर रही थीं और वेतन जारी कराने का दबाव बना रही थीं।

NIA डिप्टी SP तंजील अहमद हत्याकांड में HC का बड़ा फैसला, आरोपी रैयान की फांसी की सजा रद्द; कोर्ट ने कहा- तुरंत रिहा करो

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चर्चित NIA डिप्टी SP मोहम्मद तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना हत्याकांड में एक बार फिर सनसनीखेज फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बिजनौर की सेशन कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा को रद्द करते हुए आरोपी रैयान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. साथ ही तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

2 अप्रैल 2016 की रात बिजनौर जिले के स्योहारा थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव के पास यह वारदात हुई. NIA के डिप्टी स्क तंजील अहमद अपनी पत्नी फरजाना और दो छोटे बच्चों के साथ स्योहारा से अपनी भांजी की शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. उनकी वैगनआर कार को दो बाइक सवार हमलावरों (मुनीर अहमद और रैयान) ने रोका और अंधाधुंध गोलीबारी कर दी।

डिप्टी SP के 28 गोलियों के निशान मिले थे

तंजील अहमद की मौके पर ही मौत हो गई. उनके शरीर में 28 गोली के निशान थे. फरजाना गंभीर रूप से घायल हुईं और 10 दिन बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी मौत हो गई. दोनों बच्चे कार की पिछली सीट पर थे और नीचे छिप गए थे, जो इस भयानक घटना के चश्मदीद गवाह बने।

संपत्ति विवाद में हुआ था मर्डर

शुरू में इस हत्याकांड को आतंकवादी साजिश का एंगल दिया गया, क्योंकि तंजील अहमद देश के कई बड़े टेरर केसों की जांच कर रहे थे, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि यह व्यक्तिगत दुश्मनी और संपत्ति विवाद का मामला था. मुख्य आरोपी स्थानीय गैंगस्टर मुनीर अहमद और तंजील अहमद के बीच पुरानी रंजिश थी।

2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी

2022 में बिजनौर सेशन कोर्ट ने मुनीर और रैयान को दोषी ठहराते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी. मुनीर अहमद की 2022 में ही जेल में किडनी इंफेक्शन से मौत हो गई थी. रैयान ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. आज हाई कोर्ट ने रैयान की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा देते समय गंभीर त्रुटि की है. अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से भरा हुआ था. गवाहों के बयान अस्पष्ट और विरोधाभासी थे. कोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा. रैयान सात अप्रैल 2016 से लगातार जेल में बंद था. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद परिवार में खुशी की लहर है. वहीं तंजील अहमद परिवार कोर्ट के इस उलटफेर से सकते में है।

कानपुर किडनी कांड में नए किरदार का खुलासा, डकैती के आरोप में जेल में बंद था रैकेट का राजदार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

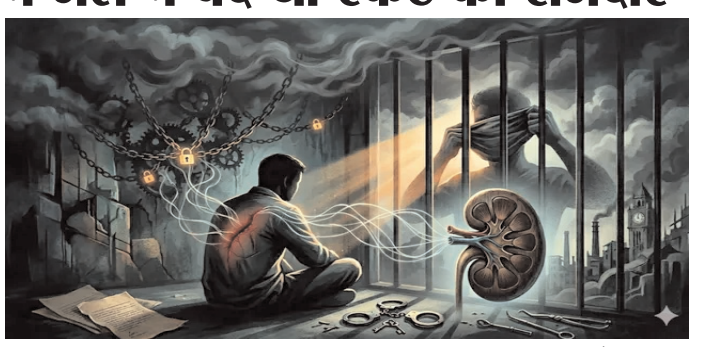

कानपुर। किडनी खरीदने-बेचने व अवैध ढंग से ट्रांसप्लांट करने के प्रकरण में सोमवार को नया किरदार एलएलआर अस्पताल का वार्ड ब्वाय अजय सामने आया है, जो दलाल शिवम अग्रवाल का साथी है। मेडीलाइफ अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए महिला को भर्ती कराने के लिए उसने ही दलाल के माध्यम से संचालक से अपने फोन से बात कराई थी। बाद में ट्रांसप्लांट के बाद हालत बिगड़ने पर दिल्ली में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने सोमवार को दलाल शिवम के बयान दर्ज करने व सात दिनों के कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। कोर्ट ने मंगलवार को जेल में दलाल के बयान लेने की अनुमति दी है।

वहीं, किडनी कांड के बड़े राजदार मेरठ के कार चालक परवेज सैफी के बारे में जानकारी हुई कि वह ढाई साल डकैती के आरोप में भी जेल में बंद रहा। सैफी ने बताया कि ओटी मैनेजर अली ड्रग्स का लती है और नशे के इंजेक्शन लगाता है। आठ माह पहले सीएमओ द्वारा सील किए गए केशवपुरम स्थित मेडीलाइफ अस्पताल में ही दिसंबर 2025 में महिला का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। हालांकि, अस्पताल संचालक नरेंद्र व रोहन ने पुलिस को बताया कि घाटा होने पर अस्पताल बंद कर दिया था। महिला को भर्ती कराने के लिए एलएलआर अस्पताल के वार्ड ब्वाय अजय ने शिवम के जरिये संपर्क किया था, तब स्वयं को गार्ड बताया। अजय खुद को डॉक्टर बताता था।

2022 में उसने अपना स्टार हास्पिटल खोला था, जिसमें औरैया के नरेंद्र व कन्नौज के रोहन ने एक साल नौकरी भी की थी। उसमें अवैध तरह से गर्भपात कराने का भी काम होता था। कई बार स्वास्थ्य विभाग ने जांच की, लेकिन कार्रवाई नहीं की। बाद में अस्पताल बंद कर दिया था। अजय ने बताया कि शिवम एंबुलेंस चालक है, तभी एलएलआर अस्पताल आते-जाते उससे संपर्क हुआ। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद अजय को नोटिस देकर छोड़ दिया है। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि दलाल शिवम के बयान व रिमांड मिलने के बाद पूरे नेटवर्क व आरोपितों का पर्दाफाश हो सकेगा। शिवम व प्रयागराज के दलाल नवीन पांडेय के पास किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से जुड़े कई सवालों के जवाब हैं। किडनी बेचने वाला आयुष सात दिन, खरीदने वाली पारुल तोमर, उसका पति विकास व भाई दिव्यांक कल्याणपुर में 15 दिनों तक रुके थे। पुलिस मामले में डॉ. प्रीति आहूजा, उनके पति आहूजा अस्पताल के संचालक डॉ. सुरजीत कुमार आहूजा समेत आठ आरोपितों को जेल भेज चुकी है। डॉ. अफजाल अहमद, अली, डॉ. रोहित, डॉ. वैभव, अमित उर्फ अनुराग, नवीन पांडेय, साहिल की तलाश कर रही है।

यूपी में आसमान से अचानक क्यों गिरने लगे गिद्ध 28 की तड़प-तड़प कर मौत; भयावह मंजर देख सन्न रह गए लोग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिजुआ (लखीमपुर)। भीरा वन रेंज के पड़रिया बीट क्षेत्र में लापरवाही और जहरखुरानी ने प्रकृति के संतुलन पर सीधा हमला कर दिया। सेमरिया गांव के पास एक किसान के खेत में जहर देकर मारे गए कुत्ते के शव को खाने से करीब 40 गिद्धों के झुंड में से 28 की तड़प-तड़प कर मौत हो गई, जो गिद्ध पर्यावरण को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, वही इंसानी लापरवाही का शिकार हो गए। सुबह जब खेत में गिद्धों का झुंड मरे कुत्ते को नोचता दिखा तो लोगों में उत्साह था, कई प्रकृति प्रेमी उन्हें कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में यह दृश्य भयावह हो गया। एक-एक कर गिद्ध बेहोश होकर गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा झुंड मौत के मुंह में समाने लगा, जिसने भी यह मंजर देखा वह सन्न रह गया।

जांच में सामने आया कि पास के गांव में आवारा कुत्तों को जहर दिया गया था, उन्हीं में से एक कुत्ता खेत के पास आकर मर गया, जिसे खाने पहुंचे गिद्ध जहर की चपेट में आ गए, नतीजा ये हुआ कि एक साथ 28 गिद्धों की मौत हो गई जबकि कई अन्य खेतों और पेड़ों के नीचे तड़पते मिले। गिद्ध, जिन्हें 'प्रकृति के सफाईकर्मी' कहा जाता है, पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन उनकी इस तरह हो रही मौतें वन्यजीव संरक्षण पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं, स्थानीय लोगों और प्रकृति प्रेमियों ने वन विभाग की सुस्ती पर भी नाराजगी जताई, उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो कई गिद्धों की जान बचाई जा सकती थी। घटना की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृत गिद्धों को एकत्र कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, कि आखिर कब तक जहरखुरानी से वन्यजीवों की यूं ही मौत होती रहेगी, और जिम्मेदार महकमे केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहेंगे?

वक्फ के नए नियम: इतिहास बदलने और भविष्य गढ़ने वाले कदम

[वक्फ संपत्तियां अब सच्चे लाभार्थियों तक: नया कानून, नई आशा]

[वक्फ का नवजागरण: पारदर्शिता और सामुदायिक शक्ति का संगम]

जब कोई कानून केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहकर समाज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वास्तविक बदलाव लाता है, तभी उसका ऐतिहासिक महत्व अमिट हो जाता है। राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के साथ वक्फ संशोधन कानून ने भारतीय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की दिशा में एक निर्णायक और क्रांतिकारी कदम है। पुराने तंत्र में भ्रष्टाचार, मनमानी और अतिक्रमण ने संपत्तियों से मिलने वाले वास्तविक लाभ को लगातार रोके रखा था। अब वक्फ बोर्ड आधुनिक तकनीक, उत्तरदायी प्रबंधन और समावेशी दृष्टिकोण के साथ काम करेगा। इसका असर केवल संपत्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी उन्मूलन जैसी मूलभूत जरूरतों में सीधे दिखाई देगा। यह परिवर्तन करोड़ों मुस्लिम परिवारों के लिए सुरक्षा, विश्वास और समृद्धि का एक नया संदेश लेकर आया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पहले अनियमितताओं और विवादों की लंबी श्रृंखला रही, जिसने उनकी वास्तविक उपयोगिता और विकास को लगातार बाधित किया। मनमाने दावे, लंबित मुकदमे और अतिक्रमण ने कई संपत्तियों को विवादास्पद और अनुपयोगी बना दिया था। अब डिजिटल पोर्टल और ऑटोमेशन के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति का पूरा जीवनचक्र ट्रैक किया जाएगा। पंजीकरण, लेखा-जोखा, ऑडिट और मुकदमेबाजी सभी ऑनलाइन और पारदर्शी होंगे। छह माह के भीतर सभी संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हो जाएंगी, जिससे कोई भी संपत्ति छिपी नहीं रहेगी। यह पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करेगी और वक्फ बोर्ड को एक वैज्ञानिक, उत्तरदायी और आधुनिक संस्था में परिवर्तित कर देगी। परिणामस्वरूप, संपत्तियों का उपयोग अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और न्यायसंगत ढंग से सुनिश्चित होगा।

जिला कलेक्टर को संपत्ति सर्वेक्षण और विवाद समाधान की जिम्मेदारी दी गई है, जो प्रबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगा। अब निर्णय केवल सरकारी रिकॉर्ड और निष्पक्ष जांच पर आधारित होंगे। अतिक्रमण स्वतः रोका जाएगा और संपत्तियां उनके वास्तविक लाभार्थियों तक सुरक्षित रूप से पहुंचेगी। कलेक्टर का समयबद्ध और तथ्यपरक दृष्टिकोण हर निर्णय को मज़बूत और भरोसेमंद बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप, वक्फ संपत्तियां शीघ्र और प्रभावी कल्याण कार्यों में लगेंगी। विवाद कम होंगे, संपत्तियों का विकास तेज़ी से होगा और गरीब, विधवा एवं वंचित वर्गों तक लाभ सुनिश्चित रूप से पहुंचेगा। यह व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को नई ऊँचाई पर ले जाएगी।

समावेशिता और संतुलित नेतृत्व अब वक्फ बोर्ड की नई पहचान बन चुका है। बोर्ड में अब कम से कम दो मुस्लिम महिलाएं और गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य होगा। इससे निर्णय प्रक्रिया व्यापक दृष्टिकोण वाली, संतुलित और संवेदनशील बनेगी। महिलाओं की भागीदारी प्रबंधन में संवेदनशीलता और सूझबूझ लाएगी, जबकि गैर-मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक निगरानी और सहयोग सुनिश्चित करेंगे। यह संरचना वक्फ को केवल धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्व का सशक्त प्रतीक बनाएगी। प्रत्येक वर्ग का सक्रिय योगदान विकास की दिशा में सुनिश्चित होगा और कल्याण कार्यों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

संपत्ति दान और वक्फ गठन के नए नियम इसे सुरक्षित, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाते हैं। अब केवल पाँच वर्ष से इस्लाम का पालन करने वाला वास्तविक और सच्चा मालिक ही संपत्ति वक्फ कर सकेगा। 'वक्फ बाय यूजर' जैसी पुरानी और असुरक्षित प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वारिसों और महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार अब सुनिश्चित और संरक्षित हैं। यह प्रावधान मनमानी और दुरुपयोग को रोकता है और दानकर्ताओं के विश्वास को सुदृढ़ करता है। संपत्तियों की संख्या बढ़ेगी और उनका उपयोग स्पष्ट, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित होगा। यह कदम वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को समाप्त करते हुए समुदाय में भरोसा, स्थिरता और सुरक्षा की नई भावना पैदा करेगा।

विवाद समाधान प्रक्रिया में सुधार न्याय की गति को तेज करेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अब ट्रिब्यूनल के फैसलों पर हाईकोर्ट में अपील का अधिकार होगा, जिससे निर्णय अधिक भरोसेमंद और न्यायपूर्ण बनेंगे। बोर्ड का सीईओ अब संयुक्त सचिव स्तर का होगा, जो पेशेवर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। म्यूटवाल्ली (वक्फ संपत्ति का प्रबंधक या देखभालकर्ता) की योग्यता और प्रशिक्षण में कड़ाई आई है, जिससे भ्रष्ट तत्वों की रोकथाम होगी। यह व्यवस्था विवादों को कम करके संपत्तियों को शीघ्र और प्रभावी विकास कार्यों में लगवाएगी। परिणामस्वरूप, समुदाय का विश्वास और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे, और संपत्तियां वास्तविक कल्याण कार्यों में सही तरीके से उपयोग होंगी।

डिजिटल निगरानी और पारदर्शी प्रबंधन के माध्यम से वक्फ संपत्तियां अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी उन्मूलन में निर्णायक और स्थायी योगदान देंगी। हर निर्णय, योजना और संपत्ति का उपयोग सीधे समुदाय की भलाई, विकास और समग्र कल्याण के लिए किया जाएगा। यह परिवर्तन मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाते हुए पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरक और मॉडल उदाहरण प्रस्तुत करेगा। भविष्य में वक्फ बोर्ड एक आदर्श और मानक संस्था के रूप में उभरेगा, जहां दक्षता, समर्पण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व साथ-साथ संचालित होंगे। इस नए ढांचे में हर संपत्ति का उपयोग न्यायसंगत, सुव्यवस्थित और विकासोन्मुख तरीके से सुनिश्चित और सुदृढ़ रूप से किया जाएगा।

राष्ट्रपति की मंजूरी ने वक्फ को नई ऊँचाइयों की ओर मजबूती से अग्रसर कर दिया है। अब प्रबंधन आधुनिक, निष्पक्ष और कल्याणकारी दृष्टिकोण से संचालित होगा। संपत्तियां अब केवल निजी संपत्ति नहीं, बल्कि भारत की साझा और अमूल्य राष्ट्रीय विरासत बनेंगी। यह नया युग आशा, समृद्धि और सतत विकास का होगा। हर वक्फ संपत्ति केवल जमीन या भवन नहीं, बल्कि समाज सेवा, न्याय और समग्र विकास का सशक्त प्रतीक बनेगी। यह कानून स्पष्ट रूप से सिद्ध करेगा कि सच्चा सुधार हमेशा समुदाय और राष्ट्र की भलाई करता है और वक्फ संपत्तियों को भविष्य में प्रगति और समृद्धि की नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

ईरान में संचार अंधकार का दौर सत्ता, संघर्ष और समाज के बीच टूटता संवाद

मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और टकराव के बीच ईरान में एक और गंभीर स्थिति सामने आई है, जहां संचार व्यवस्था का ठप हो जाना अब एक नए संकट के रूप में उभर रहा है। पिछले सैंतीस दिनों से देश में संचार सेवाओं पर लगा प्रतिबंध न केवल आम नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह शासन, सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच गहरे संघर्ष को भी उजागर करता है। यह स्थिति केवल तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक कारणों का जटिल मिश्रण छिपा हुआ है।

ईरान में यह संचार बंदी ऐसे समय में लागू की गई है, जब देश बाहरी हमलों और आंतरिक अस्थिरता दोनों का सामना कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते टकराव ने वहां की सरकार को सुरक्षा के नाम पर कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। सरकार का मानना है कि संचार माध्यमों के जरिए अफवाहें, गलत सूचनाएं और विरोध को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए संचार सेवाओं को सीमित या पूरी तरह बंद करना एक रणनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।

लेकिन इस निर्णय का प्रभाव केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ा है, जो अपने परिवार, मित्रों और बाहरी दुनिया से कट चुके हैं। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य आवश्यक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। छोटे व्यापारी, छात्र और पेशेवर लोग सबसे अधिक संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके कामकाज का बड़ा हिस्सा संचार पर निर्भर करता है। ऐसे में यह संचार बंदी एक प्रकार से सामाजिक और आर्थिक जीवन को ठहराव की स्थिति में ले आई है।

इस स्थिति का एक और पहलू अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। जब संचार माध्यम बंद हो जाते हैं, तो लोगों की आवाज भी सीमित हो जाती है। वे अपनी समस्याएं, विचार और विरोध खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। इससे समाज में असंतोष और निराशा बढ़ने की संभावना रहती है। इतिहास गवाह है कि जब लोगों की आवाज दबाई जाती है, तो वह किसी न किसी रूप में और अधिक तीव्रता के साथ सामने आती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि इस तरह की लंबी संचार बंदी नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि, ईरान सरकार का तर्क है कि यह कदम अस्थायी है और देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन सैंतीस दिनों का लंबा समय इस अस्थायी उपाय को एक स्थायी संकट का रूप देता जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम को यदि व्यापक संदर्भ में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि संचार आज केवल सूचना का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह शक्ति और नियंत्रण का एक

महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। जो इसे नियंत्रित करता है, वह समाज की दिशा और गति को भी प्रभावित कर सकता है। ईरान में हो रही यह घटना इसी बात का उदाहरण है कि कैसे तकनीक का उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव हैं।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, जहां एक ओर देशों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सूचना का प्रवाह भी एक युद्ध का रूप ले चुका है। इस सूचना युद्ध में सच्चाई और भ्रम के बीच अंतर करना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में किसी देश द्वारा संचार को पूरी तरह बंद करना एक तरह से इस युद्ध से बचने का प्रयास भी हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी और जटिल होते हैं।

ईरान की स्थिति यह भी दर्शाती है कि आधुनिक समाज में संचार का महत्व कितना अधिक हो गया है। आज के समय में यह केवल सुविधा नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। इसलिए जब इसे अचानक छीन लिया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईरान इस स्थिति से कैसे बाहर निकलता है। क्या सरकार संचार सेवाओं को बहाल करेगी या यह प्रतिबंध और लंबा खिंचेगा, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। अंतरराष्ट्रीय दबाव, आंतरिक हालात और सुरक्षा की स्थिति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अंततः, यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीक और सत्ता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जहां एक ओर सुरक्षा आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि इन दोनों के बीच संतुलन नहीं बनाया गया, तो इसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है।

ईरान में जारी यह संचार अंधकार केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक चेतावनी है कि आधुनिक युग में सूचना और संचार कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। इसे नियंत्रित करने के प्रयास हमेशा विवाद और असंतोष को जन्म देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस दिशा में संतुलित और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाया जाए, ताकि सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों का सम्मान बना रहे।

कांतिलाल मांडोत

भारत में कैंसर से त्राहिमाम हो रहा बचपन

भारत में कैंसर से जीवन गंवाने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है इनमे भी बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। तमाम कोशिश नाकाम बन रही है वहीं बच्चों के लिए कैंसर की बीमारी बेहद घातक बन रही है। दुनिया भर में बच्चों में कैंसर एक गंभीर और बढ़ती हुई चिंता बनता जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसके ज्यादातर मामले और मौतें गरीब और मध्यम आय वाले देशों में हो रही हैं. द लैंसेट में पब्लिश ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2023 स्टडी ने इस असमानता को लेकर कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में दुनिया भर में बच्चों में कैंसर के लगभग 3.77 लाख नए मामले सामने आए, जबकि करीब 1.44 लाख बच्चों की मौत हो गई, यह बीमारी बच्चों में मौत के प्रमुख कारणों में शामिल हो चुकी है और खसरा, टीबी और एचआईवी एड्स जैसी बीमारियों से भी ज्यादा जान ले रही है।

आपको बता दें कि दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का अंतर आज भी मासूमों की जान ले रहा है। चिकित्सा जगत की प्रतिष्ठित पत्रिका 'लैंसेट' की एक ताजा रिपोर्ट ने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, बचपन में होने वाले कैंसर (कर्क रोग) के 85 प्रतिशत नए मामले कम और मध्यम आय वाले देशों में सामने आ रहे हैं, लेकिन डराने वाली बात यह है कि इन देशों में मौतों का आंकड़ा कुल वैश्विक मौतों का 94 प्रतिशत है। यानी संसाधनों के अभाव में गरीब देशों के बच्चे इलाज मिलने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं।

दक्षिण एशिया इस संकट का बड़ा केंद्र बना हुआ है, जहां दुनिया के कुल चाइल्डहुड कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 20.5 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया गया. इसके अलावा, 1990 से 2023 के बीच इन मौतों में करीब 16.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी देखी गई है. हालांकि एक पॉजिटिव पहलू यह भी है कि वैश्विक स्तर पर मौतों में कुछ कमी आई है, लेकिन इसका लाभ सभी देशों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है. उच्च आय वाले देशों में इलाज बेहतर होने से बच्चों के बचने की संभावना ज्यादा है, जबकि गरीब देशों में समय पर जांच और इलाज की कमी बड़ी बाधा बन रही है.

इस स्टडी की प्रमुख लेखक लिसा फोर्स कहती हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता के कारण ही यह अंतर पैदा हो रहा है. देर से डायग्नोसिस, जरूरी इलाज की कमी और स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरियां बच्चों की जान जोखिम में डाल रही हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चाइल्डहुड कैंसर के 85 प्रतिशत नए मामले और 94 प्रतिशत मौतें इन्हीं लो और मिडिल इनकम देशों में होती हैं. इसके अलावा डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का भी 94 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं देशों में दर्ज किया गया, जो यह दिखाता है कि बीमारी का असर सिर्फ मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की जिंदगी की क्वालिटी पर भी पड़ता है.

हाल ही में आइ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज' रिपोर्ट के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि साल 2023 में दुनिया भर में बचपन में कैंसर के 3,77,000 नए मामले आए, जिनमें से 1,44,000 बच्चों की मौत हो गई। यह बीमारी आज वैश्विक स्तर पर बच्चों की जान लेने वाला आठवां सबसे बड़ा कारण बन चुकी है।

आपको हैरत होगा कि मौतों के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। 2023 में बच्चों की मौतों का वैश्विक आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा भारत 17,000 मौतें चीन 16,000 मौतें नाइजीरिया में 9,000 मौतेंपाकिस्तान मे 9,000 मौतें हुई है। अध्ययन में एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। 1990 के मुकाबले वैश्विक स्तर पर बच्चों में कैंसर से होने वाली मौतों में 27 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।इस वैश्विक रिपोर्ट में एक सकारात्मक पहलू भी है। 1990 में बचपन के कैंसर से लगभग 1.97 लाख मौतें हुई थीं। तब से लेकर अब तक दुनिया भर में मौतों के इस आंकड़े में 27 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन एक बड़ी चिंता यह भी है कि जहां पूरी दुनिया में मौतों का ग्राफ नीचे गिरा है, वहीं अफ्रीका में इसमें 55.6 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विश्लेषण कहता है कि यह सुधार समान नहीं है। जहां विकसित देशों में बेहतर तकनीक से बच्चों को बचाया जा रहा है, वहीं अफ्रीका में संसाधनों की भारी कमी के चलते कैंसर से होने वाली मौतों में 55.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। संसाधनों की कमी वाले इलाकों में बचपन का कैंसर अब बच्चों की मौत का आठवां सबसे बड़ा कारण बन चुका है।

रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों में कैंसर से होने वाली मौतों के पीछे मुख्य रूप से तीन प्रकार के कैंसर जिम्मेदार पाए गए हैं। ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) यह सबसे घातक साबित हुआ, जिससे दुनिया भर में 45,900 बच्चों की मौत हुई।दूसरा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इस कैंसर की वजह से 23,200 मासूमों ने जान गंवाई।तीसरा नॉन हॉजकिन लिंफोमा लसीका तंत्र के इस कैंसर से 15,200 मौतें दर्ज की गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह रिपोर्ट केवल आंकड़े नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। भारत जैसे देशों में, जो निम्न-मध्यम आय वर्ग में आते हैं, कैंसर मौतों में बचपन के कैंसर का योगदान 11वें स्थान पर है। इसका सीधा मतलब है कि अगर इन देशों में समय पर जांच (अर्ली डायग्नोसिस) और बुनियादी उपचार की सुविधाएं सुधारी जाएं, तो हजारों बच्चों को मौत के मुंह से निकाला जा सकता है। फिलहाल, संसाधनों की सीमित उपलब्धता ही इन मासूमों के जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे बड़ी दीवार बनी हुई है।

भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे जागरूकता और सख्त नियमन की कमी तथा हर स्तर पर बरती जा रही अनदेखी जिम्मेदार है। सामान्यतः एक भारतीय जो भोजन ग्रहण करता है, उसकी सटीक जांच की न तो कोई फिक्र है और न ही कोई ऐसी व्यवस्था उसके आसपास मौजूद है, जिससे वह आसानी से भोजन में छिपे जहर की पड़ताल कर सके।हाल में बंगलुरु स्थित 'गट-हेल्थ स्टार्टअप माइक्रोबायोटीएक्स' के कराए गए शोध में सामने आया है। देश के नौ राज्यों और 14 शहरों के 200 शहरी भारतीयों के रक्त नमूनों के विश्लेषण में पाया गया कि 78 फीसद लोग कीटनाशक अवशेषों के संपर्क में हैं।

इस अध्ययन में शामिल लोगों में से 36 फीसद में तीन या अधिक कीटनाशकों का मिश्रित असर देखा गया, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों की ओर संकेत करता है। विषाक्त पदार्थ भूजल और वायु प्रदूषण के रास्ते शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। जांच के बाद आई रपट में कहा गया है कि 54 फीसद नमूनों में एंटीबायोटिक्स और 39 फीसद में स्टेरायड पाए गए। यह हार्मोन के असंतुलन और कैंसर जोखिम बढ़ा सकता है। किसानों को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि किसी फसल पर कितनी मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि अनाजों और फल-सब्जियों में यह मात्रा इतनी रहनी चाहिए कि मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। इस तरह से 'एमआरएल' कीटनाशकों के अंधाधुंध और गलत प्रयोग पर बंदिश लगाने वाली पहली शर्त है, लेकिन सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए तमाम फलों को कार्बेट से पकाया जा रहा है यहां तक कि देश में बिकने वाले कॉल्ड ड्रिंक और ब्रेड में भी खतरनाक स्तर तक रसायन का इस्तेमाल धडल्ले से किया जा रहा है ऐसे हालात में भारत में कैंसर की महामारी का बढ़ता खतरा नियंत्रित करना संभव नहीं है। सरकार और आमजन सभी को जागरूक होना होगा।

मनोज कुमार अग्रवाल

बदलते परिवेश में स्वास्थ्य चुनौतियां

विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो न केवल स्वास्थ्य के प्रति चेतना जगाने का कार्य करता है, बल्कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयासों को भी प्रेरित करता है। इस विशेष दिन की नींव 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के साथ रखी गई थी, और इसे आधिकारिक रूप से पहली बार 1950 में मनाया गया। वर्ष 2026 में, जब दुनिया तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम 'Together for health. Stand with science' यानी 'स्वास्थ्य के लिए एकजुट। विज्ञान के साथ खड़े रहें' निर्धारित की गई है। यह थीम एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर हमारे सामने आई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं, मिथकों और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच एक निरंतर संघर्ष देखा गया है। यह विषय हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम अपने जीवन और स्वास्थ्य के प्रति निर्णय लेते समय भावनाओं या अफवाहों के बजाय साक्ष्य-आधारित विज्ञान को आधार बनाएं। विज्ञान ही वह प्रकाश है जिसने मानवता को सबसे अंधेरे समय में रास्ता दिखाया है, और 2026 का यह अभियान इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ने की एक सशक्त पुकार है।

इतिहास देखें तो वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग की यात्रा 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई थी। वर्ष 1851 में पेरिस में आयोजित पहला अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन इस दिशा में पहला बड़ा कदम था, जिसका उद्देश्य हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकना था। इसके बाद 1902 में पैन-अमेरिकन सैनिटरी ब्यूरो और 1907 में ऑफिस इंटरनेशनल डी'हाइजीन पब्लिक जैसे संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग की नींव को और मजबूत किया। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, तब यह महसूस किया गया कि एक ऐसी वैश्विक संस्था की आवश्यकता है जो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के पूरी मानवता के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। परिणामस्वरूप, 1946 में न्यूयॉर्क में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए और अंततः 7 अप्रैल 1948 को यह संगठन अस्तित्व में आया। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं, जो दुनिया भर में 'Health for All' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे बड़ी सफलता 1980 में चेचक (Smallpox) का वैश्विक उन्मूलन रही है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि यदि दुनिया विज्ञान के साथ एकजुट होकर खड़ी हो, तो किसी भी असाध्य बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। इसके अलावा, पोलियो के मामलों में 99 प्रतिशत से अधिक की कमी, एचआईवी/एड्स के उपचार में प्रगति और हाल के वर्षों में मलेरिया के पहले टीके (RTS,S/AS01) की मंजूरी विज्ञान की ही गौरवशाली उपलब्धियां हैं।

वर्ष 2026 की थीम 'Stand with science' केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता है। आधुनिक युग में डिजिटल मीडिया के विस्तार के साथ स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाएं (Infodemic) एक नई महामारी की तरह उभरी हैं। टीकाकरण से लेकर कैंसर के उपचार तक, लोग अक्सर वैज्ञानिक प्रमाणों के स्थान पर अवैज्ञानिक दावों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे में यह थीम दुनिया को याद दिलाती है कि विज्ञान ने ही हमें टीके, एंटीबायोटिक्स, उन्नत सर्जिकल तकनीक और जीवन रक्षक दवाएं दी हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति सम्मान और शोध में निवेश ही वह मार्ग है जिससे भविष्य की महामारियों को रोका जा सकता है। इसके साथ ही, 2026 का अभियान 'One Health' दृष्टिकोण पर बहुत अधिक जोर देता है। विज्ञान हमें बताता है कि मनुष्यों का स्वास्थ्य अकेले नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि यह पशुओं और हमारे साझा पर्यावरण के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। डेटा बताते हैं कि मनुष्यों में होने वाली लगभग 75 प्रतिशत नई उभरती संक्रामक बीमारियां 'जूनोटिक' होती हैं, यानी वे जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं। इसलिए, जब हम विज्ञान के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, जैव-विविधता की रक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना भी शामिल है। आज वैश्विक स्वास्थ्य के सामने चुनौतियां पहले से कहीं अधिक जटिल हैं। गैर-संचारी रोग जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और श्वसन संबंधी बीमारियां वर्तमान में दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों का लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा हैं। डेटा के अनुसार, प्रत्येक वर्ष लगभग 41 मिलियन लोग इन बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें से 17 मिलियन मौतें 70 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती हैं। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि हमारी जीवनशैली और वैज्ञानिक परामर्श की अनदेखी हमें किस ओर ले जा रही है। विशेष रूप से मधुमेह की समस्या एक वैश्विक संकट बन चुकी है, जिससे दुनिया भर में 530 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं और यह संख्या 2045 तक बढ़कर 780 मिलियन होने का अनुमान है। मानसिक स्वास्थ्य भी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर 2026 के इस अभियान में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 8 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मानसिक विकार के साथ जी रहा है। डिप्रेशन और चिंता न केवल व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी हर साल खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाते हैं। 'Stand with science' का संदेश हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि मानसिक रोग भी शारीरिक रोगों की तरह ही वैज्ञानिक उपचार और सामाजिक समर्थन के पात्र हैं।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, जैसे 2014 में पोलियो मुक्त घोषित होना और हाल के वर्षों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज करना। हालांकि, चुनौतियां अभी भी शेष हैं। भारत की एक बड़ी आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जहां गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एक संघर्ष है। डेटा बताते हैं कि भारत में गैर-संचारी रोगों का बोझ तेजी से बढ़ रहा है और यह कुल मौतों के 60 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं स्वास्थ्य सेवा को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वैज्ञानिक जागरूकता की कमी अभी भी एक बाधा है। 2026 की थीम भारतीय संदर्भ में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें स्वच्छता, पोषण और संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक सोच को जमीनी स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रम सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अशुद्ध पानी और स्वच्छता की कमी के कारण होने वाली बीमारियां अभी भी विकासशील देशों में मृत्यु का एक बड़ा कारण हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों को वैज्ञानिक रूप से समझना अब और भी जरूरी हो गया है। वायु प्रदूषण को ही लें, जो प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर लगभग 7 मिलियन अकाल मौतों के लिए जिम्मेदार है। यह न केवल फेफड़ों की बीमारियों बल्कि हृदय रोग और स्ट्रोक का भी एक प्रमुख कारक है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छरों से फैलने वाले रोगों का भौगोलिक विस्तार हो रहा है। विज्ञान हमें चेतावनी दे रहा है कि यदि हमने पर्यावरण के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया, तो आने वाले दशकों में स्वास्थ्य प्रणालियां ढह सकती हैं। 2026 का अभियान सरकारों और अंतरराष्ट्रीय निकायों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे स्वास्थ्य नीतियों को जलवायु क्रिया के साथ जोड़ें। यदि हमें सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर तीसरे लक्ष्य 'स्वस्थ जीवन और खुशहाली' को साकार करना है, तो वैज्ञानिक नवाचार और वैश्विक समन्वय का मार्ग अपनाना आज की अनिवार्य आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन केवल बड़े भाषणों या सम्मेलनों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में जब विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सिद्धांतों और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सिखाया जाता है, तो वे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। स्वास्थ्य शिविरों, टीकाकरण अभियानों और मुफ्त जांच कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिन की सार्थकता को जमीन पर उतारा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। संतुलित आहार, नियमित शारीरिक व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन जैसी छोटी-छोटी चीजें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीके हैं जिनसे हम एक लंबी और स्वस्थ आयु प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि आधुनिक तकनीक और दवाएं केवल बीमारी के उपचार में मदद करती हैं, जबकि स्वस्थ जीवनशैली बीमारी को रोकने का सबसे प्रभावी वैज्ञानिक तरीका है। अंततः, विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और एक स्वस्थ समाज ही प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हमें इस दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि हम विज्ञान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखेंगे, भ्रामक सूचनाओं से बचेंगे और स्वास्थ्य को अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे। स्वास्थ्य ही वह आधार है जिस पर हमारे सभी सपने और सफलताएं टिकी हैं। यदि हम विज्ञान और सहयोग के हाथ थामकर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर पाएंगे जहां 'Health for All' केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता होगी। यह दिवस हमें निरंतर यह प्रेरणा देता रहे कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक धरोहर है जिसे हमें वैज्ञानिक सोच और एकजुटता के साथ सुरक्षित रखना है।

महेन्द्र तिवारी

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

बैलगाड़ी से कुचलकर बुजुर्ग महिला की मौत

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के पिलखा गांव मे एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। आवारा सांड के हमले से बेकाबू हुई बैलगाड़ी ने एक वृद्ध महिला की जान ले ली, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गांव निवासी सुशीला (65) पत्नी दयाराम दोपहर में खेत से घर लौट रही थीं। वह पैदल आगे चल रही थीं। इसी दौरान गांव के पास अचानक एक आवारा सांड ने बैलगाड़ी पर हमला कर दिया। सांड को देख बैल बुरी तरह भड़क गए और तेज दौड़ने लगे, जिससे बैलगाड़ी अनियंत्रित हो गई। स्थिति बिगड़ते देख चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई और आगे चल रही महिला को हटने के लिए आवाज लगाई। लेकिन जब तक सुशीला कुछ समझ पातीं, तब तक बेकाबू बैलगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

बलिया में फॉर्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रशासन अलर्ट: 6 से 15 अप्रैल तक विशेष कैंप, हर दो घंटे में होगी मॉनिटरिंग

डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने दिए निर्देश, गांव-गांव अभियान चलाकर इस माह 100% रजिस्ट्री का लक्ष्य

बलिया में फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान को तेज गति देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गंगा बहुउद्देशीय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर 6 से 15 अप्रैल तक जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए जनपद, तहसील और ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। इन कंट्रोल रूम के माध्यम से हर दो घंटे में प्रगति की समीक्षा की जाएगी, ताकि कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई न हो। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कैंप की सूचना पहले से ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई जाए, जिससे अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। साथ ही किसानों को कैंप तक लाने के लिए सफाई कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और कोटेदारों का सहयोग लेने को भी कहा गया। लेखपालों को विशेष जिम्मेदारी देते हुए डीएम ने कहा कि जिन किसानों के नाम खतौनी में गलत दर्ज हैं या अंश निर्धारण में त्रुटि है, उसे तत्काल ठीक किया जाए, ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। उन्होंने कम प्रगति वाले गांवों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 6 से 15 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान का लक्ष्य इसी माह 100 प्रतिशत फॉर्मर रजिस्ट्री पूर्ण करना है। उन्होंने सभी अधिकारियों से पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए 15 अप्रैल तक लक्ष्य हासिल करने की अपील की। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन, सभी एसडीएम, बीडीओ, लेखपाल, उप कृषि निदेशक मनीष कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आईजीआरएस के समयबद्ध निस्तारण में कानपुर नगर को लगातार दूसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान

कानपुर। माह मार्च 2026 की आईजीआरएस (IGRS) मासिक रैंकिंग में पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर ने लगातार दूसरे महीने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि कमिश्नरेट के सभी 52 थानों द्वारा जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के परिणामस्वरूप हासिल हुई है। उल्लेखनीय है कि माह फरवरी 2026 में भी कमिश्नरेट कानपुर नगर प्रथम स्थान पर रहा था। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल द्वारा आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु दिए गए निर्देशों का प्रभावी अनुपालन किया गया, जिसके फलस्वरूप कार्यप्रणाली में सुधार आया और शिकायतों का बेहतर निस्तारण संभव हुआ।

माह मार्च 2026 में संतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत 94.09 रहा, जिसमें 30 में से 30 अंक प्राप्त हुए, जबकि आवेदकों से संपर्क का प्रतिशत 96.18 रहा, जिसमें 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए। इस उपलब्धि पर पुलिस आयुक्त द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, सभी थानों के आईजीआरएस कर्मियों को जोन स्तर पर संबंधित पुलिस उपायुक्त द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे तथा आईजीआरएस प्रभारी एवं चारों जोनों के प्रभारियों को पुलिस आयुक्त द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं केस रिवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा जनसुनवाई एवं आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

मोहनलालगंज मे बैंक ऑफ इंडिया बना अव्यवस्थाओं का केंद्र, एक कैशियर के भरोसे टिका हजारों ग्राहकों का बोझ

● .....छह माह से बैंकिंग सेवाएं बेपटरी, घंटों कतार में खड़े होने को मजबूर ग्रामीण; इकलौते कैशियर पर काम का अत्यधिक दबाव।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा इन दिनों अपनी बदहाली और चरमराती व्यवस्थाओं के कारण क्षेत्रीय जनता के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। पिछले लगभग छह महीनों से इस महत्वपूर्ण शाखा का पूरा बैंकिंग ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आ रहा है। आलम यह है कि हजारों ग्राहकों के लेनदेन की जिम्मेदारी मात्र एक काउंटर के भरोसे छोड़ दी गई है, जिससे बैंक परिसर में हर दिन अफरा-तफरी का माहौल रहता है।

भीषण गर्मी और उमस के बीच, दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसान, मजदूर और असहाय बुजुर्ग सुबह से ही बैंक के बाहर लंबी कतारों में लग जाते हैं। एक ही खिड़की होने के कारण काम की गति अत्यंत धीमी है, जिसके चलते लोगों को अपनी ही मेहनत की कमाई निकालने या जमा करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था के कारण न केवल ग्राहकों का समय और श्रम बर्बाद हो रहा है, बल्कि धक्का-मुक्की और कतारों में लगने को लेकर आए दिन बैंक परिसर में तीखी नोकझोंक और हंगामे की स्थिति बनी रहती है।

कर्मचारी पर बढ़ता मानसिक दबाव और सुरक्षा का जोखिम

इस पूरी अव्यवस्था का सबसे त्रासद पहलू यह है कि बैंक के कैशियर मनोज कुमार पिछले छह महीनों से अकेले ही हजारों ट्रांजैक्शन संभाल रहे हैं। सूत्रों की मानें तो अकेले पूरे क्षेत्र का कैश हैंडल करना और दिन के अंत में पाई-पाई का मिलान करना उनके लिए अत्यधिक मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकिंग जैसे संवेदनशील कार्य में एक ही व्यक्ति पर इतना बोझ डालना न केवल उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि यह मानवीय चूक और सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़े जोखिम को निमंत्रण दे रहा है।

प्रबंधन की उदासीनता और जनता का आक्रोश

जब इस गंभीर अव्यवस्था पर शाखा प्रबंधक का पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने घिसे-पिटे 'स्टाफ की कमी' वाले तर्क का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। प्रबंधक ने स्वीकार किया कि कर्मचारियों की कमी है, लेकिन इस संकट के समाधान के लिए उच्चाधिकारियों को औपचारिक रूप से अवगत कराया गया है या नहीं, इस पर उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बैंक प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये और संवेदनहीनता ने स्थानीय निवासियों के धैर्य का बांध तोड़ दिया है। क्षेत्रीय जनता और व्यापारिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अतिरिक्त काउंटर नहीं खोले गए और स्टाफ की कमी को दूर नहीं किया गया, तो वे उच्च स्तर पर शिकायत करने के साथ-साथ विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल, मोहनलालगंज की यह शाखा बैंकिंग सेवा के नाम पर ग्राहकों के धैर्य की परीक्षा ले रही है।

तेज हवा में उड़ी टीन शेड, कोटेदार के सिर पर गिरी; हालत नाजुक

लालगंज (रायबरेली)। तेज हवा का झोंका एक परिवार पर भारी पड़ गया। रालपुर गांव में रविवार की शाम को टीन शेड उड़कर एक व्यक्ति के सिर पर गिर गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। गांव निवासी कोटेदार राजेंद्र प्रसाद घर के बाहर खड़े थे। तभी दरवाजे पर लगी टीन शेड अचानक हवा में उखड़ गई। देखते ही देखते शेड उनके सिर पर आ गिरी। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। इमरजेंसी में तैनात डॉ. कुमार विमल ने बताया कि घायल अचेत अवस्था में लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत नाजुक बनी हुई है।

जिला रजक कंपू समिति के पूर्व मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार कनौजिया डिप्टी कलेक्टर कृतिका चौधरी का भव्य स्वागत किया

● लखनऊ राजधानी लखनऊ की कृतिका चौधरी, पुत्री विनोद कुमार चौधरी, निवासी इंदिरा नगर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ, ने अपने दूसरे प्रयास में डिप्टी कलेक्टर पद पर 30वां स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वे पिछले 6 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। कृतिका की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई तथा उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में स्नातक किया है। उनके पिता विनोद कुमार चौधरी डाक विभाग में डाक सहायक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता सुनीता चौधरी स्नातक एवं गृहिणी हैं। परिवार में शिक्षा और मेहनत का विशेष महत्व रहा है। उनकी बड़ी बहन ऋतिका चौधरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि छोटी बहन अक्षिता चौधरी स्नातक नर्सिंग की पढ़ाई के साथ-साथ नीट की तैयारी कर रही हैं। इस उपलब्धि पर परिवार के सदस्य, रिश्तेदार एवं क्षेत्रवासियों के साथ-साथ रजक समाज में भी खुशी की लहर है। इस सफलता पर दिनेश कुमार कनोजिया सहित अन्य सम्मानित व्यक्तियों ने भी कृतिका चौधरी को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर हरीश धोबी वाला, मनोज चौधरी, अजय कनोजिया, राम कुमार, अशोक कनोजिया (पत्रकार) एवं रामशंकर मौजूद रहे और सभी ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ कि राज्य परिषद की बैठक का हुआ आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 6 अप्रैल, 2026 उत्तर प्रदेश वित्तविहीन शिक्षक सेवा सुरक्षा एवं कल्याण बोर्ड/आयोग के गठन किए जाने की मांग आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में जय नारायण इंटर कॉलेज, लखनऊ के सभागार में संपन्न राजपरिषद की बैठक में सर्वसम्मति से की गई और इसे राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। संगठन के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा. आर. पी. मिश्र एवं महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 02 मई, 2026 को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय* *निरीक्षक कार्यालयों पर धरना होगा जिसमें एनपीएस शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण, शिक्षकों के बकाया अवशेषों का भुगतान, शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियां, चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान प्रकरणों का निस्तारण, शिक्षकों को उत्पीड़न से बचाए जाने, पुरानी पेंशन से आच्छादित शिक्षकों की एनपीएस कटौती को जीपीएफ खाते में जमा कराना आदि प्रमुख मांगे है। शिक्षक नेताओं ने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 एवं 18 की वापसी, पुरानी पेंशन की बहाली, विद्यालयों के कारण शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, 22 मार्च, 2016 की राज्य की राजाज्ञा से आच्छादित एवं विनिमित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने, वंचित तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण आदि से संबंधित मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। बैठक में 31 मार्च, 2026 को सेवानिवृत शिक्षक एवं शिक्षकाओं के पेंशन, जीपीएफ आदि देयकों के भुगतान की मंडलवाद समीक्षा की गई।

बैठक के अंत में संगठन के प्रदेशीय मंत्री श्री कृष्ण यादव के दुःखद निधन पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी, विधान परिषद में नेता शिक्षक दल ध्रुव कुमार त्रिपाठी, एमएलसी सहित सभी उपस्थित शिक्षक नेताओं, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज की बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी, नेता शिक्षक दल ध्रुव कुमार त्रिपाठी, एमएलसी, पूर्व एमएलसी एवं संरक्षक जगवीर किशोर जैन, महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, संरक्षक इंद्रासन सिंह, ठाकुर प्रसाद यादव, पूर्व एमएलसी डा .प्रमोद कुमार मिश्र प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं उपभोक्ता डा. आरपी मिश्र, हेमराज सिंह गौर, शिवकुमार यादव, देव भाष्कर तिवारी, अवधेश सिंह बृजेश राय, प्रदेशीय मंत्री डा.आर.के. त्रिवेदी, ज्ञानेश कुमार राय, प्रभाकर राय के साथ सभी मंडलीय अध्यक्ष/मंत्री, जिलाध्यक्ष/ जिलामंत्री, सदस्य राज्य परिषद आदि उपस्थित थे।

डीजी अग्निशमन सुजीत पांडे को फोन और महज 10 मिनट में पहुंच गई मदद

● बंथरा के डीके पैलेस के बगल में लगी थी आग, स्थानीय अग्निशमन अधिकारी का नहीं उठा फोन, फोन पर सूचना मिलते ही तुरंत हरकत में आए डीजी अग्निशमन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। बन्थरा थाना क्षेत्र के डीके के बगल में सोमवार को भीषण आग लग गई जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष चन्दर सिंह राठौर से कहा जिस पर भाजपा नेता ने अग्नि शमन नादरगंज फोन मिलाया लेकिन फोन रिसीव नही हुआ। आग इससे पहले विकराल रूप धारण कर पाती किसी के द्वारा इसकी सूचना डीजी अग्निशमन सुजीत पांडे को फोन पर दे दी। डीजी अग्निशमन सेवा से बात करने के महज 10 मिनट बाद ही अग्निशमन की गाड़ियां आग बुझाने के लिए निकल पड़ी और आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझने पर लोगों ने राहत की सांस ली। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने डीजी अग्निशमन को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ऐसे कर्मठ और तेज तर्रार अफसर हो तो बड़ी से बड़ी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुजीत पांडे जहां जिस पद पर रहे उन्होंने बखूबी पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे वो लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर रहें हो या एडीजी जोन लखनऊ या फिर सीबीआई जैसे विभागों में। वो हमेशा सरकार की मंशा पर खरे उतरे हैं। स्थानीय लोगों ने भी डीजी अग्निशमन सेवा सुजीत पांडे को धन्यवाद ज्ञापित किया। लोगों ने कहा इतने बड़े अफसर ने एक बार में सीयूजी नंबर रिसीव कर लिया और तत्काल राहत पहुंचाने का कार्य किया। जिससे आग पर काबू पाया जा सका। यहां तो छोटे अधिकारी फोन रिसीव नहीं करते फिलाहल आग से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई।

चलाकापुर गांव में भीषण अग्निकांड के बाद पीड़ित ग्रामीणों की मदद के लिए राहत का जारी

बिसवां/सीतापुर: चलाकापुर गांव में भीषण अग्निकांड के बाद पीड़ित ग्रामीणों की मदद के लिए सदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राहत कार्य जारी है। इस दौरान रिंकू रस्तोगी द्वारा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई। अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री, कपड़े एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। इस मौके पर रिंकू रस्तोगी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। ग्रामीणों ने राहत सामग्री मिलने पर आभार व्यक्त किया और प्रशासन से भी जल्द से जल्द उचित सहायता की मांग की है।

ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाने का संकल्प: शहजाद अहमद खान बने भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ (संवाददाता): भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने संगठन को और अधिक मजबूत एवं प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पत्रकार शहजाद अहमद खान को जिला मीडिया प्रभारी की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। यह निर्णय संगठन के विस्तार, किसानों की आवाज को सशक्त करने और जनसंपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। यूनियन के जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा ने शहजाद अहमद खान को आधिकारिक मनोनयन पत्र सौंपकर उन्हें इस पद पर नियुक्त किया और उनके उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

नियुक्ति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा ने कहा कि शहजाद अहमद खान लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और समाज के विभिन्न मुद्दों, खासकर किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। उनकी कार्यशैली, जिम्मेदारी के प्रति गंभीरता और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि शहजाद अपने अनुभव और मेहनत के बल पर संगठन की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में सफल होंगे और किसानों की आवाज को मजबूती प्रदान करेंगे। आलोक वर्मा ने आगे कहा कि वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में एक सक्षम और अनुभवी व्यक्ति का मीडिया प्रभारी के रूप में होना संगठन के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि शहजाद अहमद खान संगठन को वैचारिक स्तर के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे और किसानों के हितों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे।

अपनी नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए शहजाद अहमद खान ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'संगठन ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उसे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को भारतीय किसान यूनियन से जोड़ा जाए, ताकि किसानों की आवाज को और बुलंद किया जा सके। मैं संगठन की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करूंगा।

उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में किसानों की समस्याएं कई स्तरों पर सामने आ रही हैं, जिनके समाधान के लिए एक मजबूत और संगठित मंच की आवश्यकता है। भारतीय किसान यूनियन इस दिशा में लगातार प्रयासरत है और वह भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए किसानों की समस्याओं को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

शहजाद अहमद खान को जिला मीडिया प्रभारी बनाए जाने की खबर मिलते ही क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। यूनियन के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे संगठन के लिए सकारात्मक कदम बताया। कई लोगों ने कहा कि शहजाद की नियुक्ति से संगठन की गतिविधियों को नई गति मिलेगी और किसानों के मुद्दों को अधिक प्रभावी तरीके से उठाया जा सकेगा। स्थानीय निवासियों और यूनियन से जुड़े लोगों ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि शहजाद अहमद खान अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे और संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कुल मिलाकर, यह नियुक्ति भारतीय किसान यूनियन के लिए एक सशक्त कदम मानी जा रही है, जिससे संगठन की पकड़ और प्रभाव दोनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

लेखपाल से समीक्षा अधिकारी बन मुनीन्द्र त्रिपाठी ने बढ़ाया क्षेत्र का मान

वर्तमान में सिद्धार्थनगर जिले में लेखपाल के पद पर कार्यरत रहे मुनीन्द्र त्रिपाठी

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत हनुमानगढ़िया निवासी मुनीन्द्र नाथ त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। मुनीन्द्र त्रिपाठी का चयन विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। उन्होंने प्रदेश स्तर पर 22वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है, जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत हनुमानगढ़िया टोला कोनघुसरी निवासी शिक्षक राधेश्याम त्रिपाठी के पुत्र मुनीन्द्र त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा पंडित मुक्तिनाथ जूनियर हाईस्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने नौतनवा इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट और राजीव गांधी महाविद्यालय ललाईन पैसिया से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। मुनीन्द्र त्रिपाठी वर्तमान में सिद्धार्थनगर जिले में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और अब राजपत्रित अधिकारी बनकर सफलता की नई इबारत लिखी है। उनकी इस उपलब्धि पर पिता राधेश्याम त्रिपाठी, माता पूजा देवी, देवेंद्र नाथ त्रिपाठी, नागेंद्र प्रसाद शुक्ल, रविंद्र नाथ त्रिपाठी, सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, विनय कुमार पाण्डेय, सदा मोहन और विजय कुमार मद्धेशिया समेत क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उनकी इस सफलता पर परिजनों और मित्रों ने खुशी व्यक्त की है। ऐसे में मुनीन्द्र त्रिपाठी की सफलता युवाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत है।

भागवत कथा के छठवें दिन गोवर्धन लीला एवं महा रास की कथाओं को सुन भावुक हुए श्रोता

● निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करने से सुधरता है जन्म और मरण-पंडित चंद्रेश कृष्ण शास्त्री

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली। अखरी पोस्ट कसेरुवा में सप्तवेदी, गणेश आंबिका, रूद्र हनुमत देव, सहित मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मुख्य यजमान शिव सिंह, सपत्नीक किरन सिंह, के यहां आनंद मिश्रा के द्वारा संकल्पित सातवीं श्रीमद् भागवत कथा का हो रहा भव्य आयोजन। आपको बता दें कि, ग्राम सभा अखरी पोस्ट कसेरुवा जिला फतेहपुर में श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन सोमवार को श्री अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास पंडित चंद्रेश कृष्ण शास्त्री ने प्रमुख रूप से गोवर्धन लीला एवं महा रास जैसी कथाओं का व्याख्यान किया। कथा व्यास ने बताया कि, भगवान ने अपने बाएं हाथ की उंगली पर गोवर्धन को धारण किया और वृंदावन वासियों की रक्षा किया। जब इंद्र ने यह देखा तो इंद्र ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। इसके पश्चात भगवान शरद पूर्णिमा के दिन महा रास करते हैं और अंत में भगवान ने कंस का वध किया। कथा व्यास द्वारा विभिन्न प्रसंगों को सुनकर पांडाल में उपस्थित समस्त श्रोता भाव विभोर हो उठे।

इस मौके पर यज्ञ शाला के मुख्य आचार्य पंडित सीताराम शास्त्री, यज्ञाचार्य सुबोध शास्त्री, उपयज्ञाचार्य योगेंद्र नाथ त्रिपाठी, व्यवस्थापक शीतला बखूश सिंह, श्रवण मिश्रा, शेर सिंह, विजय बहादुर सिंह, राजा सिंह चौहान, अक्षत सिंह, शुभम सिंह, मोनू सिंह, विक्रम सिंह, हर्षित सिंह, निखिल सिंह, रंग बहादुर सिंह, धीरेंद्र सिंह एवं समस्त मित्रगण सहित आदि भक्त उपस्थित रहे।

समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में ग्राम मुरथना में पीडीए संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन

बिसवां (सीतापुर) समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में ग्राम मूर्थना में पीडीए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी प्रवक्ता दिग्विजय सिंह देव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने पीडीए एकता पर जोर देते हुए वर्तमान सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और समाजवादी सरकार के दौरान चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही वर्ष 2028 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में माज़ शब्बीर, श्याम यादव सहित कई नेताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान धीरेंद्र वर्मा, पिंकू वर्मा, गया प्रसाद गौतम, विनोद भार्गव, रामकिशोर भार्गव, जतीन भार्गव, राजकुमार वर्मा, एहतिशाम किरमानी, सदफ खान, पुष्कर तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

रामकोट संकुल के कंपोजिट विद्यालय रामकोट में शिक्षा चौपाल सम्पन्न

● हमें अपने दायित्वों को प्रथम वरीयता में निपटाना चाहिए तथा बच्चों को प्रेम की भाषा से समझाना चाहिएः- संतोष कुमार मिश्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर संकुल रामकोट के कंपोजिट विद्यालय रामकोट में शिक्षा चौपाल का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी श्री संतोष मिश्रा जी की अध्यक्षता एवं कुशल निर्देशन में संपन्न हुई। कंपोजिट विद्यालय रामकोट की प्रधान अध्यापिका श्रीमती सावित्री राज के द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। सरस्वती वंदना के साथ नवप्रवेशी बच्चों की नोडल टीचर श्रीमती सोनिया त्यागी जी ने छात्रों का माल्यार्पण एवं उपहार देकर सम्मानित किया। विद्यालय के होनहार बच्चों को विद्यालय की तरफ से उपहार प्रदान किए गए। सभी अभिवावकों का माल्यार्पण किया गया एवं जलपान कराते हुए सभी से छात्रों को नियमित रूप से विद्यालय भेजकर स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने की अपील की गयी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एस आर जी श्री आलोक श्रीवास्तव जी ने शिक्षा चौपाल की सार्थकता पर विस्तृत प्रकाश डाला। ए आर पी श्रीमती पूनम बाजपेई जी ने शिक्षा चौपाल की सराहना करते हुए विद्यालय परिवार एवं संकुल रामकोट के शिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापित किया अपने विचार व्यक्त किया। विद्यालय के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सबका मन मोहा। इस अवसर पर संकुल रामकोट के सभी प्रधान अध्यापक उपस्थित रहे। कमोजिट विद्यालय रामकोट की तरफ से उपस्थित सभी शिक्षकों को बैच लगाकर एवं पेन देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार की तरफ से सभी को जलपान कराया गया। शिक्षा चौपाल का सफल संचालन डॉ0 अनुपम मिश्र ने किया। इस अवसर पर सुशील गुप्ता, दिनेश कुमार किरन बाला, विभा गुप्ता, रजनी श्रीवास्तव, वीनू खन्ना,विपिन अवस्थी, उर्मिला, आरती शुक्ला, दीपमाला शुक्ला, मनुज सिंह, हेमराज, आकाश, दीपक वर्मा, ममता वर्मा, संगीता, सीमता सहित अनेक शिक्षक अभिभावक उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सफलताओ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे निशांत कुमार- प्रमोद कुमार पटेल जिला अध्यक्ष

गोपालगंज- बिहार के विकास पुरुष लोक प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चौथी बार जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर गोपालगंज जिला जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने उन्हें हार्दिक बधाई और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी है श्री पटेल ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में जनता दल यूनाइटेड बिहार सहित देश में सफलता के नये आयाम स्थापित करेगा न्याय के साथ विकास के संकल्प को और अधिक मजबूती एवं गति प्रदान होगी वही श्री पटेल ने कहा कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जब से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर संगठन के साथियों एवं पदाधिकारी से मिल रहे हैं इससे पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश बढ़ गया है, नीतीश कुमार के सभी गुण निशांत कुमार में दिखाई पड़ रही है श्री पटेल ने कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की विचारधारा और नीति को आगे बढ़ाने में निशांत कुमार पूर्ण रूप से सक्षम है, बिहार में सरकार और संगठन को संभालने मे निशांत कुमार सफल होंगे!

दिल्ली में LPG सिलिंडर संकट गहराया, 400 रुपये किलो तक पहुंची कीमत

नई दिल्ली। एलपीजी सिलिंडर को लेकर लोगो की दिक्कतें जारी है। केंद्र व राज्य सरकार की कवायद के बाद भी कई परिवारों तक एलपीजी की पहुंच दुरूह, कष्टप्रद व महंगा बना हुआ है। जिनके पास कनेक्शन नहीं है तो उन्हें एलपीजी प्रति किलो 400 रुपये तक में मिल रहा है। केंद्र ने प्रवासी मजदूरों द्वारा छात्रों की परेशानी को देखते हुए पांच किलो के छोटू सिलिंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है, लेकिन वह अभी एजेंसियों पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में एजेंसी संचालकों का कहना है कि अभी एलपीजी कंपनियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसमें अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। इस बीच, बाजारों से श्रमिकों का पलायन जारी है। इस संकट की मार सबसे अधिक मेहनतकश तबके पर पड़ रही है। जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि भोजन के लिए ईंधन की जरूरतें अलग अलग मोहल्लों में गैस रिफिलिंग की दुकानों के जरिए ही पूरी होती रही हैं। पर, मौजूदा स्थिति में इन दुकानों में एलपीजी 300-400 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा है। इसके साथ ही मजदूर बस्तियों में ढाबों समेत तमाम दुकानों पर खाने के दाम बढ़ चुके हैं। यह संकट अब केवल आपूर्ति या मूल्य वृद्धि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक व्यापक मानवीय और आर्थिक संकट का रूप ले चुका है, जिसके चलते राजधानी से श्रमिकों का पलायन शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर यह देखा जा सकता है। इस संकट का असर केवल मजदूरों पर नहीं बल्कि उद्योग और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना तय है।

दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राष्ट्रीय राजधानी में मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिनों के लिए तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है।

तेज हवा चलने की संभावना

दोनों दिन न केवल बादल छाए रहेंगे बल्कि 30 से 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा के कई दौर होंगे। मौसम के इस बदलाव से तापमान में भी तीन से पांच डिग्री तक की गिरावट संभावित है। दोनों ही दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है। इस बीच सोमवार को मौसम का मिश्रित मिजाज देखने को मिला।बादलों की आवाजाही के बीच धूप भी निकली रही। वर्षा कहीं नहीं हुई। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री कम 33.3 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री कम 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 80 से 27 प्रतिशत रिकार्ड हुआ। दूसरी ओर दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिलहाल साफ ही चल रही है। सोमवार को राजधानी का एक्यूआइ 135 यानी ''मध्यम'' श्रेणी में दर्ज किया गया। एक दिन पूर्व रविवार को यह 134 और शनिवार को 137 रहा था। यानी हवा लगातार ''मध्यम'' श्रेणी में ही चल रही है और हाल फिलहाल इसमें अधिक बदलाव की संभावना भी नहीं है।

तेल ले लूंगा, लेकिन...ईरान को अल्टीमेटम देते-देते ट्रंप ने बताई अपने दिल की बात

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी कि अगर तेहरान समझौता करने में विफल रहता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह उनके द्वारा तय की गई समय सीमा नजदीक आने के साथ ही उनके कड़े रुख का संकेत है। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान के लिए मंगलवार की समय सीमा अंतिम है। ट्रम्प ने कहा कि अगर वे अपना काम ठीक से करें तो यह बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। उन्हें कुछ चीजें करनी होंगी। वे यह जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वहां के लोग पहले और दूसरे चरण के पागलों की तुलना में कहीं अधिक समझदार हैं। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अस्वीकार करने के बाद उनकी ये टिप्पणियां आई।

तेहरान ने अस्थायी युद्धविराम के बजाय युद्ध का स्थायी अंत आवश्यक बताया। ईरान की प्रतिक्रिया में 10 बिंदुओं का ढांचा प्रस्तुत किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र में संघर्षों का अंत, होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन की गारंटी, प्रतिबंधों को हटाना और पुनर्निर्माण के प्रति प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के बारे में ट्रुथ सोशल पोस्ट में अपशब्दों के प्रयोग पर हुई आलोचना का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग केवल अपनी बात पर जोर देने के लिए किया था। उन्होंने कहा, केवल अपनी बात समझाने के लिए। मुझे लगता है कि आपने इसे पहले भी सुना होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि मंगलवार शाम 8 बजे (पूर्वी मानक समय) (0000 जीएमटी) तक समझौता न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिनमें तेहरान पर 'नरक' बरसाने की धमकी भी शामिल है। इस तात्कालिकता का एक कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से यातायात बहाल करना है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

तीव्र बयानबाजी के बावजूद, ईरान में बचाए गए दो अमेरिकी वायुसैनिकों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने अधिक संयमित लहजा अपनाया। उन्होंने कहा, दोनों की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। दोनों घायल हुए थे, लेकिन अब वे ठीक हैं। अपने अतिरिक्त बयान में, ट्रम्प ने कहा कि ईरान ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 'यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ब्रिटेन पर भी निशाना साधते हुए कहा, 'ब्रिटेन को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम एक और नेविल चेम्बरलेन नहीं चाहते, क्या आप सहमत हैं?

मुंबई के दिंडोशी इलाके में हुई हिंसा के बाद बीएमसी ने चलाया आरोपी के घर पर बुलडोजर

पूरे इलाके में पुलिस कड़ा बंदोबस्त किया गया बैरीकेट लगा दिया गया है पुलिस ने पूरे इलाको को छावनी बदल दिया है।

मुंबई के दिंडोशी इलाके में बीती रात दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद आज स्थिति तनाव पूर्णझड़प में 2 घायल, 1 की हालत नाजुक अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें 3 नाबालिग शामिल हैं। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हालात नियंत्रण में, शांति बनाये रखने की अपील मारी अम्मा (साउथ इंडियन) की त्रिशूल यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी भीड़ के साथ झड़प में बदल गई स्थानीय लोगों और हिंदू पक्ष में भयंकर आक्रोश हिंदू संगठन नेताओं का कहना है कि, इन लोगों का यहां पर आतंक था, कल जय श्री राम के गाने बजाने को लेकर इन लोगों ने हमला कर दिया। एक को इतना मारा है कि वह बचने की स्थिति में है। इन सबको सबक सिखाने का वक्त आ गया है।

असम विधानसभा चुनाव: श्रीभूमि में सुरक्षा बढ़ी, राताबाड़ी में प्रशासन सक्रिय

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि संवाददाता: आगामी असम विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए श्रीभूमि जिले में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। जिला प्रशासन, पुलिस और अर्धसैनिक बल संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी और नियमित गश्त बढ़ा रहे हैं, ताकि मतदाता सुरक्षित मतदान कर सकें। श्रीभूमि की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लीना दल के नेतृत्व में उच्चस्तरीय टीम ने राताबाड़ी क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ में थे रामकृष्णनगर समजेला इंचार्ज अन्सुल शर्मा, राताबाड़ी थाना के एएसपी चित्तरंजन बसुमतरी, और सीआरपीएफ के कमांडेंट सहित बड़ी सुरक्षा टीम। निरीक्षण में क्षेत्र के काजीरबाजार, दलग्राम, बाजारघाट, पाहाड़तल, पलडहर और गोलालकांडी क्षेत्रों की स्थिति देखी गई। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर मतदान से जुड़ी समस्याओं और सुविधाओं की जानकारी ली और मतदाताओं को निर्विघ्न मतदान करने की अपील की। प्रशासन की यह सक्रियता क्षेत्रवासियों का विश्वास बढ़ा रही है, और आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के अभियान जारी रहेंगे।

जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा में त्रिकोणीय महायुद्ध, आख़िरी हँसी किसकी?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि- जैसे-जैसे असम 2026 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, राज्य के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक सरगर्मी तेज़ होती जा रही है। इसी उबाल के केंद्र में अब जिले का रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र में आखिरी समय में बदलते समीकरणों ने इस सीट को पूरी तरह 'हॉट सीट' बना दिया है। निर्दल उम्मीदवार उत्तम दास की एंट्री से बदले समीकरण इस चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज़ हैं सोनबिल-नगेन्द्र नगर क्षेत्र के मूल निवासी और निर्दलीय उम्मीदवार उत्तम दास। उनकी उम्मीदवारी को शासक दल के प्रत्याशी विजय मालाकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। खासतौर पर कैवर्त समुदाय में उनकी मज़बूत पकड़ वोटों के गणित को प्रभावित कर सकती है। दूसरी और विजय बनाम सुरुचि–मुकाबले में नया मोड़

दूसरी ओर, कांग्रेस उम्मीदवार सुरुचि राय नमःशूद्र समुदाय की मज़बूत प्रतिनिधि बनकर उभरी हैं। इस समुदाय का अच्छा-खासा वोट बैंक इस क्षेत्र में मौजूद है, जो चुनाव परिणाम में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला लगभग तय कुल मिलाकर शासक दल, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार इन तीन ताकतों के बीच रामकृष्णनगर अब एक त्रिकोणीय मुकाबले का मैदान बन चुका है।

कड़े और रोमांचक संघर्ष की पूरी संभावना है, जिससे यह सीट बेहद दिलचस्प बन गई है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि 'किंगमेकर' बन सकते हैं मुस्लिम वोटर

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाता भी बेहद अहम फैक्टर हैं। उनका झुकाव जिस ओर होगा, जीत का पलड़ा उसी दिशा में झुक सकता है। आख़िरी हँसी किसकी? अब सबकी नज़र एक ही सवाल पर टिकी है आखिरि जीत का ताज किसके सिर सजेगा? विजय मालाकार, सुरुचि राय या फिर चौंकाने वाले उत्तम दास? रामकृष्णनगर की यह चुनावी जंग अब अपने चरम रोमांच पर है. आख़िरी फैसला जनता के मत से ही होगा।

प्रदेश भर के निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ केंद्र सरकार को ईमेल से पत्र भेजकर शिकायत

अभिभावकों के शोषण पर सख्त कार्रवाई की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया। प्रदेश भर के निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ और मनमानी व्यवस्था के खिलाफ अब विरोध तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश संगठन महामंत्री जितेंद्र चतुर्वेदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी एवं डॉ. सुकांत मजूमदार को ईमेल के माध्यम से विस्तृत पत्र भेजकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। अपने पत्र में उन्होंने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में प्रदेश के अधिकांश निजी स्कूल अभिभावकों को एनसीईआरटी की पुस्तकों के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। कई मामलों में इन किताबों की कीमतें सामान्य दरों से कई गुना अधिक हैं, जिससे मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

इसके साथ ही, कई विद्यालयों द्वारा पुस्तकों, कॉपियों एवं यूनिफॉर्म की बिक्री स्वयं स्कूल परिसर में ही की जा रही है या कुछ निर्धारित दुकानों से ही खरीदारी करने का दबाव बनाया जा रहा है। यदि अभिभावक अन्यत्र से सामग्री खरीदना चाहें, तो उन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते व्यवसायीकरण और अनुचित लाभ कमाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। जितेंद्र चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस गंभीर विषय पर तत्काल हस्तक्षेप करते हुए देशभर में स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने एनसीईआरटी पुस्तकों को अनिवार्य करने, किसी विशेष दुकान से खरीदारी की बाध्यता समाप्त करने, तथा पुस्तकों और यूनिफॉर्म की कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस प्रकार की मनमानी पर रोक नहीं लगाई गई, तो अभिभावकों का आर्थिक शोषण लगातार बढ़ता जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र ठोस कार्रवाई करेगी, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

CBI के शिकंजे में फंसा दिल्ली के शकरपुर थाने का हेड कांस्टेबल, रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा

पूर्वी दिल्ली। शकरपुर थाना में सोमवार को सीबीआई की टीम ने रेड डालकर एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपित हेड कांस्टेबल राहुल को फरियादी से पैसे लेते समय ही हिरासत में लिया गया। जानकारी के अनुसार, फरियादी ने आरोप लगाया था कि उसके काम के बदले हेड कांस्टेबल रिश्वत की मांग कर रहा था। इसकी शिकायत सीबीआई से की गई, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर ट्रैप लगाया। जैसे ही राहुल ने पैसे लिए, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। सीबीआई की टीम फिलहाल शकरपुर थाने के अंदर ही आरोपित से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

भाजपा स्थापना दिवस पर लहराए ध्वज विकास और राष्ट्रवाद पर जोर

● पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार कर रही भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं अपितु दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी

परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद से दूर, भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के साथ कार्यकर्ता ही सर्वोपरि

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमेठी। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद सहित क्षेत्रभर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। पार्टी कार्यालयों के साथ-साथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने-अपने घरों पर पार्टी का ध्वज फहराकर इस दिवस को गौरवपूर्ण तरीके से मनाया। इस अवसर पर पार्टी के प्रति समर्पण, संगठन की मजबूती और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराया गया।स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश चंद्र शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुदृढ़ करने वाला एक सशक्त संगठन है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के मूल विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का कार्य आज तेजी से हो रहा है। देश के कोने-कोने में बुनियादी ढांचे का विकास, गरीब कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, इन सभी उपलब्धियों का श्रेय वर्तमान नेतृत्व को जाता है।गिरीश चंद्र शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने सदैव संगठन को सर्वोपरि मानते हुए कार्य किया है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी ने निरंतर प्रगति की है और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है और वैश्विक स्तर पर देश की छवि लगातार सुदृढ़ हो रही है। विदेशी निवेशकों का भारत की ओर बढ़ता रुझान इस बात का प्रमाण है कि देश आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। आज प्रदेश विकास और निवेश के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है और औद्योगिक हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। पार्टी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान' के सिद्धांत पर कार्य करते हुए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता भी अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर संगठन के शीर्ष पदों तक पहुंच सकता है। सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। स्थापना दिवस के इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में देशभक्ति और संगठनात्मक एकजुटता का संदेश स्पष्ट रूप से देखने को मिला।

सीता ग्रुप ऑफ एजूकेशन की 'सुपर-40' योजना का परिणाम घोषित

चयनित विद्यार्थियों का भव्य सम्मान

महमूदाबाद-सीतापुर लगातार दो वर्षों तक प्रदेश को टॉपर देने वाली संस्था सीता ग्रुप ऑफ एजूकेशन द्वारा संचालित 'सुपर-40' योजना के तहत आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित किया गया। इसके उपरांत कॉलेज के शास्त्री सभागार में कक्षा 6, 9 और 11 के चयनित 40-40 विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संस्था के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने बताया कि गरीब और जरूरतमंद मेधावी छात्रों को बेहतर निश्शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। इस वर्ष सीतापुर समेत रेउसा, लहरपुर, सिधौली, तंबौर, हरगांव, सांडा सकरन सहित बाराबंकी, लखीमपुर, हरदोई और लखनऊ आदि जनपदों के 45 विद्यालयों से 718 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 702 छात्र-छात्राएं 31 मार्च को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए। 6 अप्रैल को घोषित परिणाम में कक्षा 6, 9 और 11 के 40-40 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। संस्था ने चयनित सभी विद्यार्थियों की कक्षा 12 तक निश्शुल्क शिक्षा का जिम्मा लिया है।

सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहला विकासखंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामलाल यादव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक राजाराम यादव, कार्यक्रमाध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी अवधराम मौर्य, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेश वर्मा, सीएचसी महमूदाबाद के अधीक्षक डॉ. आशीष वर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को माल्यार्पण, बैज अलंकरण एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर वाजपेयी, मनोज श्रीवास्तव, रामानुज दीक्षित, उप प्रधानाचार्य नीरज वर्मा, अंजली वर्मा, शिवसेवक मिश्र, राकेश शुक्ल सहित सैकड़ों अभिभावक और विद्यार्थी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कूटरचित वेबसाइट बनाकर एवं वेबसाइट पर अवैध रूप ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। थाना प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-46/2025 धारा-318(4)/319(2)/338/336(3)/340(2)/61(2)/112 भा0न्या0सं0 व 66(घ)/74/84(सी) आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. मो0 राशिद पुत्र स्व0 हकीमुद्दीन स्थाई पता हरसौली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर हालपता 3/71 गली नं0 08 रमेश पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली 2. समीर पुत्र स्व0 अली मोहम्मद स्थायी पता ईदगाह कॉलोनी पक्का घाट थाना बागपत जिला बागपत उत्तर प्रदेश हालपता जे-555 गली नं0 01 बुध बाजार स्वरुप नगर दिल्ली को साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक-06.04.2026 को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी । मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित 05 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

घटना का विवरण- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओरिजिनल वेबसाइट 222.ह्वश्चद्वह्यश्च.द्दश्रह्व.द्बठ्ठ की कूटरचित वेबसाइट 222.ह्वश्चद्वह्यश्च-द्दश्रह्व.द्बठ्ठ बनाकर एवं वेबसाइट पर अवैध रूप विद्यार्थियों/अभिभावको को अनुचित भुगतान के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह के काल सेन्टर का पर्दाफाश किये जाने के सम्बन्ध में।

अपराध का तरीका- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणो से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि हम लोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओरिजिनल वेबसाइट 222.ह्वश्चद्वह्यश्च.द्दश्रह्व.द्बठ्ठ की कूटरचित वेबसाइट 222.ह्वश्चद्वह्यश्च-द्दश्रह्व.द्बठ्ठ बनाकर तथा उ0प्र0 व अन्य प्रदेशो के भिन्न- 2 विश्वविद्यालय व तकनीकि शिक्षा बोर्ड की कूटरचित अंक पत्र,डिग्री,डिप्लोमा व प्रव्रजन प्रमाण पत्र बनाकर सम्पूर्ण भारत वर्ष में एजूकेशनल संस्थान/छात्र/छात्राओं को वितरित करते है। गिरोह के अन्य सदस्यों द्वारा फर्जी अंक पत्र,डिग्री,डिप्लोमा व प्रव्रजन प्रमाण पत्र मांग के अनुरूप स्वयं बनाकर व कलर प्रिंटआउट निकालकर फर्जी मोहर लगाकर एजूकेशनल संस्थान/छात्र/छात्राओं दे देते थे। फर्जी अंक पत्र,डिग्री,डिप्लोमा व प्रव्रजन प्रमाण पत्र की डिटेल मुख्य अभियुक्त शशि प्रकाश राय के माध्यम से कूटरचित 222.ह्वश्चद्वह्यश्च-द्दश्रह्व.द्बठ्ठ व अन्य वेबसाइट के डाटाबेस में अपलोड करा कर एजूकेशनल संस्थान/छात्र/छात्राओं को आनलाइन वेरिफाई करा देते थे। जिससे अंक पत्र/डिग्री/डिप्लोमा व प्रव्रजन प्रमाण पत्र के फर्जी होने की शंका एजूकेशनल संस्थान/छात्र/छात्राओं की दूर हो जाती थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मो0 राशिद पुत्र स्व0 हकीमुद्दीन स्थाई पता हरसौली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर हालपता 3/71 गली नं0 08 रमेश पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली, उम्र करीब 34 वर्ष।
2. समीर पुत्र स्व0 अली मोहम्मद स्थायी पता ईदगाह कॉलोनी पक्का घाट थाना बागपत जिला बागपत उत्तर प्रदेश हालपता जे-555 गली नं0 01 बुध बाजार स्वरुप नगर दिल्ली, उम्र करीब 33 वर्ष।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक आयोजित

● लक्ष्य के अनुरूप खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमेठी। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद वर्ष 2026-27 को सफलतापूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में संचालित सभी क्रय एजेंसियों के अधिकारी, केंद्र प्रभारी तथा मंडी सचिव उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में चल रही गेहूं खरीद की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए एजेंसीवार खरीद की जानकारी प्राप्त की। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ?2585 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि जनपद अमेठी में गेहूं खरीद के लिए कुल 106 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 30 मार्च से 15 जून तक खरीद की जाएगी। इनमें विपणन शाखा के 38, पीएसएफ के 20, पीसीयू के 20, यूपीएसएस के 17, भारतीय खाद्य निगम के 4, नैफेड के 5 तथा मंडी समिति के 2 क्रय केंद्र शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसानों से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए प्रतिदिन अधिक से अधिक गेहूं खरीद सुनिश्चित की जाए, ताकि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर देते हुए निर्देशित किया कि कांटा, छन्ना, नमी मापक यंत्र, पर्याप्त बोरे, स्वच्छ पेयजल एवं छाया की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए टोकन प्रणाली के आधार पर खरीद की जाए। साथ ही उन्होंने महिला एवं वृद्ध किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी केंद्र प्रभारियों को किसानों को जागरूक करने पर बल देते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसानों को सरकारी खरीद प्रक्रिया से जोड़ा जाए, जिससे न केवल किसानों को लाभ मिले बल्कि जनपद में गेहूं खरीद का लक्ष्य भी पूर्ण किया जा सके। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से क्रय केंद्रों की निगरानी करें और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें, जिससे खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके।